



डिजिटल क्रांति : हर क्षेत्र तक कनेक्टिविटी

डॉ. निमिष कपूर

भारत का ग्रामीण परिदृश्य डिजिटल प्रौद्योगिकियों के माध्यम से एक ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। पिछले एक दशक में इंटरनेट कनेक्टिविटी के विस्तार, डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, फिनटेक नवाचारों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के अनुप्रयोगों ने गाँवों की अर्थव्यवस्था और समाज को नया रूप दिया है। ग्रामीण और शहरी भारत के बीच डिजिटल अंतर तेजी से कम हो रहा है। अब लाखों लोगों को ऑनलाइन सेवाओं, बाजारों और ज्ञान तक पहुँच मिल रही है। यह क्रांति संचार के अलावा कृषि, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, वित्तीय समावेशन और शासन जैसे क्षेत्रों को भी प्रभावित कर रही है। गाँव अब डिजिटल रूप से सक्षम होकर नवाचार और उद्यमिता के नए केंद्र के रूप में उभर रहे हैं।

ग्रा

मीण भारत में डिजिटल क्रांति इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल अवसंरचना के तेजी से विस्तार द्वारा संचालित हो रही है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे गतिशील डिजिटल इकोसिस्टम में से एक है। हालिया अनुमानों के अनुसार, भारत की डिजिटल पहुँच तेजी से बढ़ रही है, जहाँ 958 मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं और अनुमान है कि 5G के निरंतर विस्तार के साथ यह संख्या वर्ष 2026 के अंत तक 1.03 बिलियन तक पहुँच सकती है। यह जानकारी 'इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2025' में दी गई है, जिसे जनवरी 2026 में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) ने वैश्विक डेटा कंपनी कान्टार (Kantar) के सहयोग से जारी किया है।

ग्रामीण भारत में लगभग 548 मिलियन (57%) उपयोगकर्ता हैं, जो शहरी क्षेत्रों की तुलना में लगभग चार गुना तेजी से इंटरनेट वृद्धि को आगे बढ़ा रहे हैं। उपयोग के पैटर्न भी इस बदलाव को

दर्शाते हैं— ग्रामीण उपयोगकर्ता शहरी उपयोगकर्ताओं की तुलना में शॉर्ट-फॉर्म वीडियो अधिक देखते हैं, जहाँ 588 मिलियन लोग नियमित रूप से इनका उपयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग 44% उपयोगकर्ता वॉयस सर्च जैसी एआई सुविधाओं का प्रयोग कर रहे हैं, जो दर्शाता है कि ग्रामीण भारत नई तकनीकों को कितनी तेजी से अपना रहा है। ये निष्कर्ष इंडिया कंज्यूमर एंड यूसेज बिहेवियर सर्वे 2025 के अनुरूप हैं, जिसमें 400 शहरों और 1,000 गाँवों में 87,000 से अधिक लोगों का सर्वेक्षण किया गया। यह सर्वे एक स्पष्ट बदलाव दर्शाता है: अब ग्रामीण भारत तकनीक के मामले में पीछे नहीं है बल्कि यह डिजिटल उपकरणों के उपयोग में अग्रणी बनकर देश के डिजिटल भविष्य को दिशा दे रहा है।

मोबाइल नेटवर्क के विस्तार ने इस परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। 4G नेटवर्क लगभग 95% आबादी तक पहुँच चुका है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अब डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुँच मिल रही है। इस प्रगति

लेखक एक वैज्ञानिक और विज्ञान सम्प्रेषक हैं, जिन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार और जनसंपर्क के क्षेत्र में ढाई दशकों से अधिक का अनुभव है। ईमेल: nimish2047@gmail.com

का बड़ा हिस्सा 'डिजिटल इंडिया मिशन' के तहत चलाए जा रहे सरकारी कार्यक्रमों से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था बनाना है।

भारतनेट: ग्रामीण डिजिटल अवसंरचना की रीढ़

भारतनेट दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड परियोजनाओं में से एक है जो 2.15 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को उच्च गति वाली ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ रहा है। इसके माध्यम से गाँवों को ई-गवर्नेंस, टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल बैंकिंग और ई-कॉमर्स जैसी सेवाओं तक पहुँच मिल रही है। साथ ही, इस परियोजना के तहत 2.5 लाख पंचायतों तक कनेक्टिविटी पहुँचाने की योजना है।

भारतनेट प्रगति रिपोर्ट 2025 के अनुसार, 2.18 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें अब सेवा-तत्पर हैं यानी डिजिटल सेवाएं देने के लिए तैयार हैं और देश में 6.92 लाख किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल केबल फाइबर का जाल बिछाया जा चुका है।

भारतनेट कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को सीधे ग्रामीण घरों तक पहुँचाना है। यह कनेक्टिविटी लोगों को विभिन्न प्रकार की सेवाओं तक पहुँच प्रदान कर रही है, जैसे ऑनलाइन सरकारी सेवाएँ (ई-गवर्नेंस), स्वास्थ्य के लिए टेलीमेडिसिन, छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल बैंकिंग और ई-कॉमर्स। स्थिर और तेज इंटरनेट उपलब्ध कराकर भारतनेट देशभर के गाँवों में सीखने, व्यवसाय करने और आवश्यक सेवाओं तक पहुँच के नए अवसर खोल रहा है।

कॉमन सर्विस सेंटर: ग्रामीण भारत के डिजिटल द्वार

कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) ग्रामीण डिजिटल सेवाओं की रीढ़ हैं, जो गाँव-स्तर पर सरकारी योजनाओं, वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल साक्षरता तक पहुँच प्रदान करते हैं। स्थानीय उद्यमियों, जिन्हें *विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स* (VLEs) कहा जाता है, द्वारा संचालित CSCs डिजिटल द्वार के रूप में कार्य करते हैं, जिससे नागरिकों को आवश्यक सेवाओं से सीधे जुड़ने के लिए दूरदराज के शहरों की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

भारत में वर्ष 2025 तक, लगभग 6 लाख कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें से करीब 79% ग्राम पंचायतों में स्थित हैं। यह वर्ष 2014 के 83,000 केंद्रों की तुलना में लगभग 680% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। भारतनेट द्वारा 2.15 लाख से अधिक पंचायतों को जोड़ने के साथ, CSCs अब और भी व्यापक सेवाएँ प्रदान कर पा रहे हैं। इनमें आधार नामांकन और सत्यापन, बैंकिंग और बीमा सेवाएँ, टेलीमेडिसिन परामर्श, एग्रीस्टैक के माध्यम से कृषि सहायता और यूपीआई के जरिए डिजिटल भुगतान जैसी सेवाएँ शामिल हैं।

एक ही स्थान पर अनेक सेवाएँ उपलब्ध कराकर, कॉमन सर्विस सेंटर पहुँच से जुड़ी बाधाओं को कम करते हैं और ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए सशक्त

बनाते हैं। किसानों को सब्सिडी और फसल संबंधी सलाह दिलाने से लेकर छात्रों और उद्यमियों को ऑनलाइन साधनों के उपयोग में सक्षम बनाने तक, CSCs गाँवों को डिजिटल रूप से सशक्त समुदायों में बदल रहे हैं। सरकारी सेवाओं और नागरिकों के बीच सेतु के रूप में कार्य करते हुए ये केंद्र वित्तीय समावेशन, ई-गवर्नेंस और सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

डिजिटल शासन और समावेशी कल्याण

डिजिटल तकनीक ने सरकार के लिए ग्रामीण भारत में कल्याणकारी योजनाओं को पहुँचाना काफ़ी आसान बना दिया है। 'आधार डिजिटल पहचान प्रणाली' और 'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण' (DBT) के साथ, सब्सिडी और लाभ की राशि सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुँचाई जा रही है। इससे लीकेज कम होता है और यह सुनिश्चित होता है कि सहायता सही लोगों तक पहुँचे।

आधार सक्षम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (AeDBT) ने गाँवों में लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुँच के तरीके को बदल दिया है। बैंक खातों में सीधे पैसा भेजने से यह धोखाधड़ी को कम करता है और फर्जी लाभार्थियों को बाहर करता है। 'DBT प्रगति रिपोर्ट 2025' के अनुसार, वर्ष 2025 के मध्य तक 370 से अधिक सरकारी योजनाओं के तहत 50 करोड़ से अधिक ग्रामीण नागरिकों को 34 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है।

पीएम-किसान जैसी प्रमुख योजनाओं, जिससे लगभग 11.65 करोड़ किसान लाभान्वित होते हैं और मनरेगा में 95% से अधिक लाभार्थियों के खाते 'आधार' से जुड़े हुए हैं। इससे आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के माध्यम से रियल-टाइम सत्यापन संभव हो पाता है, जिससे गाँवों में ऑडिट के दौरान फर्जी लाभार्थियों में 20-30% तक की कमी लाने में मदद मिली है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में DBT हस्तांतरण 7.16 लाख करोड़ तक पहुँच गया, जो पिछले वर्ष के 6.3 लाख करोड़ लाभार्थियों से अधिक है। NSAP और छात्रवृत्ति जैसी ग्रामीण योजनाएँ अब लगभग 85% परिवारों को कवर कर रही हैं, जो डिजिटल वितरण प्रणालियों के बढ़ते विस्तार को दर्शाता है।

जन धन खातों, आधार और मोबाइल कनेक्टिविटी से मिलकर बनी JAM के सहयोग से ये प्रणालियाँ सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल निधि अंतरण सुनिश्चित करती हैं, जो 'सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनीटरिंग सिस्टम (CPSMS)' जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित होती हैं।

अन्य प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म भी सुशासन को और सुदृढ़ बनाते हैं। *DigiLocker* नागरिकों को अपने आधिकारिक दस्तावेज सुरक्षित रूप से संग्रहित और साझा करने की सुविधा देता है, जबकि *UMANG* विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, *e-Gram Swaraj* ग्राम-स्तर के प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।

डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन

ग्रामीण भारत में डिजिटल क्रांति का सबसे स्पष्ट प्रभाव डिजिटल भुगतानों के व्यापक उपयोग के रूप में देखा जा रहा है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) अब ग्रामीण भारत में काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है। छोटे दुकानदार, किसान और सड़क विक्रेता अब रोजमर्रा के लेन-देन के लिए QR कोड और मोबाइल ऐप्स का उपयोग कर रहे हैं।

NSO उपभोक्ता भुगतान सर्वेक्षण वर्ष 2025-26 के अनुसार, वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 86.7% ग्रामीण युवाओं ने यूपीआई का उपयोग किया, जो शहरी युवाओं के 74.4% उपयोग से अधिक है। यूपीआई का उपयोग विशेष रूप से चाय की दुकानों और छोटी दुकानों पर तेजी से बढ़ रहा है, जिसे 2,000 से कम के लेन-देन पर शून्य मर्चेट डिस्काउंट रेट (MDR) जैसी सरकारी प्रोत्साहन नीतियों से बढ़ावा मिला है।

यूपीआई के लगभग 55% लेन-देन टियर-2, टियर-3 और ग्रामीण क्षेत्रों से होते हैं, जहाँ 40% ग्रामीण उपयोगकर्ता इसे प्राथमिकता देते हैं और 38% लोग सक्रिय रूप से डिजिटल भुगतान कर रहे हैं। पिछले चार वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में UPI का उपयोग छह गुना बढ़ा है, जिसे 1,500 करोड़ (वित्त वर्ष 2024-25) के BHIM-UPI प्रोत्साहन और भारतनेट के माध्यम से बेहतर कनेक्टिविटी का समर्थन मिला है।

आज, छोटे लेन-देन के लिए भी यूपीआई को नकद से अधिक प्राथमिकता दी जा रही है, जहाँ 57% ग्रामीण उपयोगकर्ता डिजिटल भुगतान को चुनते हैं, जबकि 38% अभी भी नकद का उपयोग करते हैं। 548 मिलियन ग्रामीण इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और CSCs के सहयोग से यह तेजी से बढ़ता उपयोग नकदी पर निर्भरता को कम कर रहा है और दैनिक जरूरतों तथा सरकारी हस्तांतरणों के लिए वित्तीय समावेशन को मजबूत बना रहा है।

डिजिटल भुगतान ने गाँवों में लोगों के लिए पैसे भेजना और प्राप्त करना आसान बना दिया है, लेन-देन को पारदर्शी बनाया है और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच को सरल किया है। जन-धन खातों, मोबाइल बैंकिंग और माइक्रो-फाइनेंस प्लेटफॉर्म जैसे कार्यक्रमों के साथ मिलकर, ये डिजिटल साधन ग्रामीण नागरिकों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में भाग लेने में मदद कर रहे हैं। साथ ही, ये लोगों को अपने धन पर अधिक नियंत्रण भी प्रदान कर रहे हैं।

डिजिटल कृषि: अगला आयाम

सरकार 'एग्रीस्टैक' नामक एक डिजिटल इकोसिस्टम का निर्माण कर रही है, जो किसान डेटाबेस, भूमि अभिलेख, फसल संबंधी जानकारी और सैटेलाइट डेटा को एकीकृत करता है। इस प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा किसान आईडी (Kisan ID) है, जो एक विशिष्ट डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करता है और किसानों को विभिन्न कृषि सेवाओं से जोड़ता है।

एग्रीस्टैक में किसान आईडी, डिजिटल फसल सर्वेक्षण, डिजिटल भूमि अभिलेख और यूनिफाइड फार्म सर्विसेज इंटरफेस (FSI) जैसे प्रमुख तत्व शामिल हैं। गुजरात, उत्तर

प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने आधार OTP के माध्यम से किसान आईडी पंजीकरण के लिए पहले ही पोर्टल शुरू कर दिए हैं।

'किसान आईडी' एक 12 अंकों की विशिष्ट संख्या है, जो आधार और मोबाइल फोन से जुड़ी होती है और 20 करोड़ से अधिक किसानों को कवर करती है। यह किसानों को योजनाओं की पात्रता जाँचने, ऋण प्राप्त करने और एआई आधारित कृषि सलाह लेने में मदद करती है।

यह डिजिटल अवसंरचना सब्सिडी के लक्षित वितरण को भी संभव बनाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सहायता सही समय पर सही किसानों तक पहुँचे। साथ ही, यह फसल बीमा कवरेज को बेहतर बनाती है जिससे किसान मौसम या कीटों से होने वाले नुकसान से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्मार्ट खेती

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत विश्लेषण ग्रामीण भारत में कृषि पद्धतियों को तेजी से रूपांतरित कर रहे हैं। अब किसान एआई आधारित उपकरणों की मदद से फसलों की निगरानी कर सकते हैं, कीट प्रकोप का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं और खरपतवार प्रबंधन अधिक प्रभावी ढंग से कर पा रहे हैं।

सैटेलाइट इमेजरी और एआई एनालिटिक्स के साथ फसल निगरानी अब अधिक स्मार्ट हो गई है, जिससे फसल की खराब स्थिति का पता लगाने, उत्पादन का अनुमान लगाने और संभावित समस्याओं के बारे में किसानों को पहले से ही सतर्क करने में मदद मिलती है। इसी तरह, एआई आधारित कीट पूर्वानुमान प्रणाली मौसम के पैटर्न और ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण करके कीट प्रकोप के बारे में किसानों को चेतावनी देती है, जिससे वे समय रहते निवारक कदम उठा सकते हैं और कीटनाशकों के उपयोग को कम कर सकते हैं।

'प्रिसीजन कृषि' भी एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। सेंसर, ड्रोन और डेटा एनालिटिक्स किसानों को पानी, उर्वरक और अन्य संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग करने में मार्गदर्शन देते हैं, जिससे लागत कम होती है और उत्पादकता बढ़ती है। स्वचालित खरपतवार नियंत्रण भी तेजी से बढ़ रहा है, जहाँ एआई आधारित मशीनें खरपतवार की पहचान करके उन्हें हटाने में मदद करती हैं। इससे रासायनिक खरपतवारनाशकों की आवश्यकता कम होती है और सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिलता है।

ये नवाचार सरकार द्वारा समर्थित पहलों जैसे भारत-विस्तार, एग्रीस्टैक और इंडिया AI मिशन का हिस्सा हैं। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में ऐसे एआई आधारित उपकरणों को प्रदर्शित किया गया, जो सैटेलाइट डेटा, फसल जानकारी और स्थानीय परामर्श को कई भाषाओं में एकीकृत कर लाखों किसानों तक पहुँचा रहे हैं। डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत सेंसर नेटवर्क और एआई आधारित कीट एवं खरपतवार प्रबंधन जैसे कार्यक्रमों ने मापनीय परिणाम दिखाए हैं जैसे इनपुट लागत

और रासायनिक उपयोग में 10-30% तक की कमी, साथ ही फसल उत्पादन में वृद्धि।

सरकारी स्रोतों के अनुसार, एआई-सक्षम उपकरण अब 14 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को सहायता प्रदान कर रहे हैं, जो स्थानीय भाषाओं में रियल-टाइम सलाह देते हैं, सिंचाई और उर्वरक उपयोग को अनुकूलित करते हैं और कीटनाशक लागत को 15-20% तक कम करने में मदद करते हैं।

डिजिटल कृषि प्लेटफॉर्म और बाजार तक पहुँच

डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसानों के उत्पाद बेचने और बाजार तक पहुँचने के तरीके बदल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक 'राष्ट्रीय कृषि बाजार' (e-NAM) है, जो विभिन्न राज्यों की कृषि मंडियों को जोड़ता है और कृषि उत्पादों के ऑनलाइन व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म पारदर्शी मूल्य निर्धारण के माध्यम से किसानों को उचित मूल्य दिलाने में मदद करता है, उन्हें व्यापक बाजारों तक पहुँच प्रदान करता है और बिचौलियों की भूमिका को कम करता है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है।

किसान ई-मित्र एक एआई आधारित चैटबॉट है, जो किसानों को त्वरित कृषि सलाह प्रदान करता है। एग्री-PARAM एक उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, जिसका उपयोग कृषि अनुसंधान, जलवायु मॉडलिंग और उन्नत विश्लेषण के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एआई आधारित मूल्य पूर्वानुमान उपकरण किसानों को अपनी उपज के विक्रय के लिए उपयुक्त समय और मूल्य तय करने में सहायता करते हैं।

कृषि से परे डिजिटल परिवर्तन

डिजिटल क्रांति केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण जीवन के कई अन्य पहलुओं को भी बदल रही है। डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएँ अब दूरदराज के गाँवों तक चिकित्सा सुविधाएँ पहुँचा रही हैं, वहीं ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही, ई-कॉमर्स के अवसर ग्रामीण कारीगरों और छोटे व्यवसायों को देशभर के ग्राहकों तक पहुँचने में मदद कर रहे हैं। इस प्रकार, तकनीक ग्रामीण भारत के जीवन, सीखने और आजीविका के तरीकों को पूरी तरह से नया रूप दे रही है।

'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' भारत में एक डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है। डिजिटल हेल्थ आईडी, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड (EHR) और टेलीमेडिसिन सेवाओं के माध्यम से अब गाँवों के लोग बिना लंबी दूरी तय किए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सकते हैं। टेलीमेडिसिन विशेष रूप से दूरदराज क्षेत्रों में बहुत उपयोगी है, जहाँ अस्पताल और क्लीनिक की संख्या कम है। इसके जरिए डॉक्टर ऑनलाइन सलाह और उपचार प्रदान कर सकते हैं।

DIKSHA और e-Vidya जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण संसाधन, डिजिटल पाठ्यपुस्तक और शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल उपलब्ध करा रहे हैं। ये उपकरण ग्रामीण

स्कूलों के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री तक पहुँच प्रदान करते हैं, सीखने की कमी को दूर करने में मदद करते हैं और सीमित स्कूल अवसंरचना वाले क्षेत्रों में भी उनके समग्र शिक्षण अनुभव को बेहतर बनाते हैं।

इसी तरह, 'ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स' जैसी पहलें ग्रामीण उत्पादकों को हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद और स्थानीय वस्तुओं को ऑनलाइन बेचने में मदद कर रही हैं। इससे आय के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती मिल रही है।

ग्रामीण डिजिटल परिवर्तन में चुनौतियाँ और प्राथमिकताएँ

ग्रामीण भारत में डिजिटल क्रांति खेती, भुगतान, स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यमिता को तेजी से बदल रही है। इस प्रगति के बावजूद कुछ चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, जैसे कनेक्टिविटी की कमी, कम डिजिटल साक्षरता और डेटा सुरक्षा से जुड़ी चिंताएँ।

इन चुनौतियों का प्रभावी समाधान जरूरी है, जिससे तकनीक का लाभ वास्तविक रूप से ग्रामीण समाज तक पहुँच सके। ग्रामीण डिजिटल परिवर्तन को सतत बनाए रखने के लिए प्रमुख नीतिगत कदमों का ध्यान निम्नलिखित बिंदुओं पर होना चाहिए:

- दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में विशेष रूप से ब्रॉडबैंड अवसंरचना का विस्तार।
- डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना, ताकि नागरिक ऑनलाइन सेवाओं का आत्मविश्वास के साथ उपयोग कर सकें।
- एग्रीटेक में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को बढ़ावा देना, जिससे स्टार्टअप्स और शोध संस्थान छोटे किसानों के लिए समाधान विकसित कर सकें।
- सुरक्षित और नैतिक डेटा उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत डेटा गवर्नेंस ढाँचे को लागू करना।
- एआई आधारित ग्रामीण नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन देना, जिससे तकनीक-आधारित विकास और सतत प्रगति को बढ़ावा मिल सके।

आगे की राह

डिजिटल क्रांति ग्रामीण भारत को स्मार्ट कृषि और डिजिटल भुगतान से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यमिता तक नए रूप में ढाल रही है। नई तकनीकें किसानों, छात्रों और ग्रामीण व्यवसायों के लिए नए अवसर पैदा कर रही हैं, जिससे गाँव भारत की डिजिटल प्रगति में सक्रिय भागीदारी कर पा रहे हैं।

राष्ट्रीय एआई रणनीतियों जैसी पहलें समावेशी विकास पर विशेष ध्यान देती हैं, खासकर कृषि और ग्रामीण आजीविका के क्षेत्र में। इस प्रगति को बनाए रखने के लिए सार्वभौमिक कनेक्टिविटी, डिजिटल साक्षरता और तकनीक के उपयोग को सुनिश्चित करना आवश्यक है।

निरंतर निवेश और नवाचार के साथ, ग्रामीण भारत एक स्मार्ट, सतत और समावेशी अर्थव्यवस्था के केंद्र के रूप में उभर सकता है। □